

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों का अध्ययन

भुवनलाल टांडेकर^{1*}, डॉ. वैशाली यादव²

1 शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश

btandekar@gmail.com

2 सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश

सार

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) बहुत मददगार होते हैं, लेकिन अक्सर इनका महत्व नहीं समझा जाता। कई समितियों ने इनके वित्तीय स्थिरता और पुनर्गठन की संभावना की जांच की है। 1786 में जब जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तब भारत का वित्तीय सिस्टम अस्तित्व में आया। 1806 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो भारत का सबसे पुराना बैंक है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्रामीण क्षेत्र एक प्रमुख योगदानकर्ता है। आजकल, ग्रामीण भारतीयों के पास पहले से कहीं अधिक खर्च करने लायक पैसा है और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) लगभग एक सदी से हैं और इनके मुख्य सिद्धांत हमेशा एक-दूसरे की मदद करना, स्वतंत्रता और मिलकर काम करना रहे हैं। भारत के निजी क्षेत्र का लगभग हर बैंक और सरकारी स्वामित्व वाला हर बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है। भारत में पारंपरिक उत्पादन और खपत चक्र देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुए हैं, जो हमेशा से देश की सामाजिक और आर्थिक नींव रही है।

कीवर्ड सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, भारत, सामाजिक और आर्थिक

परिचय

बैंकिंग संस्थान सभी क्षेत्रों में व्यापारिक समुदाय को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण भी प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यापारिक समुदाय और कृषक समुदाय को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तदनुसार, यह उद्योग और कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसके बाद, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि के साथ वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसलिए, बैंकिंग संस्थान धन प्रवाह को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था में भौतिक संपत्ति बनाने में योगदान करने में सहायक है। बैंकिंग क्षेत्र जनता को आसान, सुरक्षित और सुलभ वित्तपोषण प्रदान करके दक्षता संचालित करने, वित्तीय प्रणाली में स्थिरता प्रदान करने और समान आर्थिक विकास को बढ़ाने में भी प्रभावी है। इसके अलावा, यह देश में

पूँजी निर्माण का मार्ग भी तैयार करता है। परिणामस्वरूप, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंकिंग क्षेत्र की कुशल दक्षता आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बचत और जमा निधियों के एकीकरण को बढ़ाने में सहायक है। दावा किया गया है कि कुशल बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय बचत के एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करने और भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए इन बचत का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण चालक के रूप में काम करता है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली 18वीं शताब्दी में स्थापित हुई और जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1786 में हुई। भारतीय स्टेट बैंक सबसे पुराना बैंक है जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी। 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 4 अन्य बैंकों का अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया। भारत में RBI बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करता है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक। सभी सहकारी या वाणिज्यिक बैंक जो RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, भारत में अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। सहकारी बैंक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। इसके बाद, वाणिज्यिक बैंकों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

सहकारी बैंक छोटे आकार की बैंकिंग इकाइयाँ हैं जो पिछले 100 वर्षों से शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ये बैंक लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक उल्लेखनीय क्षेत्र है जहाँ बैंकिंग और सहकारी सहयोग एक दूसरे के पूरक हैं। ये बैंक द्वि-स्तरीय प्रणाली के आधार पर और सहयोग, स्व-विकास और सामुदायिक सहायता के मानकों पर कार्य करते हैं। सहकारी बैंक छोटे ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, विशेष रूप से शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में, जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-ऋण योग्य माना जाता है। शहरी और प्रांतीय सहकारी बैंक भारत में कार्यरत सहकारी बैंकों के विभिन्न प्रकार हैं।

शहरी सहकारी बैंक, जिन्हें प्राथमिक सहकारी बैंक भी कहा जाता है, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। ये छोटे आकार की सहकारी बैंकिंग इकाइयाँ हैं जो छोटे पैमाने की व्यावसायिक इकाइयों, खुदरा विक्रेताओं, पेशेवरों, वेतन वर्गों आदि की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। निरंतर विकास के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र ने काफी संघर्ष का अनुभव किया है। ये बैंक आर्थिक असमानता और धन के संचयन की समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण धनी लोग कमजोर क्षेत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस अध्ययन में भारत में शहरी सहकारी बैंकों के विकास, उनके वित्तीय प्रदर्शन और उन सुधारों का विश्लेषण किया गया है जिनसे बैंकों के प्रदर्शन को बेहतर आर्थिक विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।

साहित्य समीक्षा

हरलया, डॉ. एट अल. (2022) बैंकिंग क्षेत्र किसी देश में कई सुविधाएं प्रदान करता है। बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय गतिविधियां सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चालक हैं। इसके बाद, किसी राष्ट्र में बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि के साथ आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। मौजूदा शोधकर्ताओं ने विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव की जांच के लिए बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों का उपयोग किया। भारत में, सीमित अध्ययन आर्थिक विकास पर बैंकिंग क्षेत्र के प्रभाव की जांच कर सके। इसलिए, यह अध्ययन 1981-2019 के दौरान समय श्रृंखला डेटा का उपयोग करके भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर बैंकिंग क्षेत्र के प्रभाव का आकलन करता है। इसने प्रति व्यक्ति जीडीपी को आश्रित चर के रूप में, और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापक मुद्रा, कुल आरक्षित अनुपात के लिए व्यापक मुद्रा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अंतिम उपभोग व्यय, अनुभवजन्य परिणामों से पता चला है कि कुल आरक्षित अनुपात में व्यापक मुद्रा, निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण, अंतिम उपभोग व्यय और साक्षरता दर का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शेट्टी, मेघा एट अल. (2022). भारत में, ग्रामीण बैंकिंग ने प्रौद्योगिकी के विकास और अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करना है, जो आमतौर पर औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उपेक्षित है। इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारतीय बैंकिंग प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर प्रकाश डालना, विलय और प्रस्तुत एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास की तुलना करना, और वर्षों से उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करना है। यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आँकड़े विभिन्न सार्वजनिक और अप्रकाशित स्रोतों से एकत्र किए गए थे, जिनमें वेबसाइट, पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और शोध पत्र शामिल हैं। अध्ययन में पाया गया कि शाखाओं की संख्या और उनके प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विस्तार और वित्तपोषण की दक्षता में वृद्धि हुई है। विलय की नई प्रणालियों ने कार्य के संदर्भ में बैंकों के रखरखाव और विस्तार में सुधार किया है। यह अध्ययन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करने के साथ-साथ विलय के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन या वृद्धि का भी एक प्रयास है।

विवोहो, जमाल एट अल. (2021). यह शोधपत्र 1860 ग्रामीण बैंकों का उपयोग करके आर्थिक विकास और गरीबी पर निधि पुनर्आबंटन के बीच संबंधों की जाँच करता है। हमारे तिमाही आँकड़े हमें 2010-2016 के बैंक-स्तरीय और प्रांतीय-स्तरीय आँकड़ों को मिलाने की अनुमति देते हैं। हम पाते हैं कि मध्यस्थता फलन के हमारे प्रतिनिधि के रूप में ऋण-जमा अनुपात आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। हमारा अरैखिक समाश्रयण दर्शाता है कि अत्यधिक वित्त क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कम करता है, लेकिन दीर्घावधि में, गरीबी कम करने में सहायक हो सकता है। हमारे परिणाम कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ प्रदान करते हैं कि ग्रामीण

बैंक आर्थिक विकास में अच्छे तरीके से योगदान दे सकते हैं, लेकिन जोखिम और प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में उन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

गौतम, राहुल एट अल. (2022). इस शोध का उद्देश्य भारत में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रभाव की जांच करना है। हम 2018 से 2020 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिए 29 भारतीय राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वितीयक डेटा का उपयोग करते हैं। इस अध्ययन में परिकल्पना का मूल्यांकन करने के लिए पैनल डेटा विश्लेषण (पीडीए) का उपयोग किया गया है। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकार को बुनियादी ढांचे और वित्तीय साक्षरता के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये दोनों गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह उल्लेखनीय आर्थिक विकास का दावा करता है और बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने वाले बुनियादी ढांचे में निवेश करके गरीबी को कम करता है।

सैयद, मज्दी. (2019) हाल के साक्ष्य बताते हैं कि वित्तीय जुटाव और वित्त तक पहुंच गरीबी कम करने की प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत में, कई प्रयासों के बावजूद, केवल 53 प्रतिशत आबादी के पास बैंक खाते हैं, जो वैश्विक औसत (69 प्रतिशत) ग्लोबल फाइंडेक्स डेटासेट, 2017) से कम है। यह पत्र भारत के ग्रामीण शाखा विस्तार कार्यक्रम के आंकड़ों का उपयोग करके ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का अनुभवजन्य प्रमाण प्रदान करता है। 1977 से 1990 के बीच, भारत के वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक द्वारा एक ऐसे स्थान पर खोलने की अनुमति दी गई थी जहाँ पहले से ही एक या अधिक बैंक शाखाएँ मौजूद थीं, केवल तभी जब वे चार खोल दें जहाँ कोई बैंक शाखाएँ नहीं थीं। इस विनियमन के कारण बैंकों ने ग्रामीण, कम विकसित भारतीय राज्यों में अधिक शाखाएँ खोलीं, जबकि इसके विपरीत हो रहा था, बैंक इस अवधि के बाहर शहरों के भीतर अपना परिचालन कर रहे थे।

सहकारी बैंक

सहकारी बैंक एक वित्तीय संस्थान होता है जो अपने सदस्यों से संबंधित होता है और इस प्रकार वे अपने बैंक के मालिक और ग्राहक दोनों होते हैं। ये बैंक सहकारी क्षेत्र में संगठित छोटी-छोटी इकाइयाँ होती हैं जो शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करती हैं और मुख्य रूप से समुदायों, क्षेत्रों और कार्यस्थलों पर केंद्रित होती हैं।

इन बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाएँ बचत और चालू खाते, सुरक्षित भंडारण स्थान, निजी और व्यावसायिक ग्राहकों को ऋण या गृह ऋण हैं। कामकाजी वर्ग के ग्राहकों के लिए, जिनके लिए बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ वे अपनी मेहनत की कमाई जमा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या टेलीफोन बैंकिंग जैसी सुविधाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं। हालाँकि ये बैंक दी जाने वाली सुविधाओं के मामले में निजी बैंकों से कमज़ोर हैं, फिर भी उनकी ऋण दरें निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी हैं। निजी बैंकों के विपरीत, दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया लंबी या कठोर होती है, और जल्दी

से ऋण स्वीकृत करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। शहरी सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के नियम वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने की तुलना में कम कठोर हैं।

वाणिज्यिक बैंक भारत में सबसे व्यापक रूप से फैल रहे बैंकिंग संगठन हैं। ये महत्वपूर्ण उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये बैंक व्यावसायिक आधार पर, समाज के लाभ के लिए चलते हैं और कई देशों में अपने संगठन, उद्देश्यों, गुणों और प्रशासन के आधार पर निवेशक बैंकों से भिन्न होते हैं। इन बैंकों का प्रबंधन और नियंत्रण बैंकिंग विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और इन्हें विवेकपूर्ण बैंकिंग दिशानिर्देशों का पालन करना होता है, जो इन्हें निवेशक बैंकों के स्तर का बनाते हैं। नियंत्रण और प्रबंधन सीधे राज्य निकायों द्वारा लागू किया जा सकता है या किसी सहकारी संघ या केंद्रीय निकाय को सौंपा जा सकता है। दूसरी ओर, एक सहकारी बैंक सहकारी निकाय के सदस्यों के एक समूह की सेवा के लिए चलाया जाता है। ये बैंक अपनी आय का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही मुनाफे के रूप में वितरित करते हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा व्यवसाय में रखते हैं। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और लगभग सभी निजी क्षेत्र के बैंक वाणिज्यिक बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में, किसी राज्य के भीतर, राज्य की राजधानी से शुरू होकर, जिला स्तर पर राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत सहकारी समितियाँ होती हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के मुद्दे

विभिन्न क्षेत्रों में विकास के बावजूद, भारत में शहरी सहकारी बैंकों को संसाधन जुटाने में सीमित दायित्व, निम्न स्तर की वसूली, उच्च लेनदेन लागत और लंबे समय से नियंत्रित ब्याज दर जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है। आजकल ये बैंक आर्थिक असमानता और धन के संकेन्द्रण के मुद्दों को हल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण मजबूत वर्ग कमजोर वर्गों का शोषण कर रहे हैं।

1. सहकारी विधान की प्रयोज्यता से उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याएँ हैं - सरकार द्वारा सहकारी समितियों पर जानबूझकर नियंत्रण, सरकार द्वारा निदेशक मंडल का नामांकन, सहकारी संस्थाओं में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदि।
2. शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), जिन्हें 1990 के दशक के अंत तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक माना जाता था, अब लगातार विफलताओं के मामलों के साथ सबसे कमज़ोर बैंकों में से एक बन गए हैं। वर्तमान में ये बैंक आकार, स्थान और किसी क्षेत्र को ऋण देने की बाध्यता के कारण अधिक असुरक्षित हो गए हैं और इस प्रकार, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से वंचित हैं।

3. वर्ष 2001 में गुजरात और आंध्र प्रदेश के शेयर बाज़ार में हुए घोटालों की श्रृंखला ने इन बैंकों पर जनता का विश्वास कम कर दिया। पूर्ण कुप्रबंधन और धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, गैर-निष्पादित आस्तियों से कोई आय नहीं होती, जिसके कारण ये बैंक अत्यंत कमज़ोर/बीमार हो गए।
4. इसके अलावा, अपनी क्षमताओं के बावजूद, शहरी सहकारी बैंक शेयर पूंजी जुटाने में बहुत कमज़ोर हैं। इस प्रकार, इस क्षेत्र के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू की गई सख्त नियामक व्यवस्था और विवेकपूर्ण बैंकिंग मानदंडों की आवश्यकताओं के कारण अपना सहकारी चरित्र बनाए रखना लगातार कठिन होता जा रहा है।
5. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में यूसीबी का असमान भौगोलिक वितरण इस तथ्य से स्पष्ट है कि इन राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों की उपस्थिति 80% से अधिक है और उनकी कुल जमा राशि का 75% हिस्सा है।
6. अधिकांश शहरी सहकारी बैंकों का कोई निवेश नहीं है। वे अपने अनुभव और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश कर रहे हैं। लेकिन अतीत में कुछ बैंकों द्वारा आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने के कुछ उदाहरण सामने आए हैं, जहाँ उन्होंने नकली दलालों से प्रतिभूतियाँ खरीदीं और अंततः निवेशित धन को भारी नुकसान पहुँचाया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत भारत के बैंक इसके अधीन हैं स्वामित्व की वित्त मंत्रित्व, इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं हालाँकि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शहरी शाखाएँ भी होती हैं। भारत सरकार ने 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप 2 अक्टूबर 1975 को पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था, जिसे सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में था।

इनका कार्यक्षेत्र भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है और यह राज्य के एक या एक से अधिक जिलों को कवर करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विभिन्न कार्य करते हैं जैसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना, वेतन वितरण जैसे सरकारी कार्य करना। एमजीएनआरईजीएकर्मचारियों और पेंशन वितरण, लॉकर सुविधा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई सेवाओं जैसी पैरा-बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना। वर्तमान में भारत भर में 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं; 'एक राज्य-एक आरआरबी' रणनीति, जिसका उद्देश्य 43 आरआरबी को 28 बैंकों में समेकित करके लागतों को युक्तिसंगत बनाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है, को वित्त मंत्रालय द्वारा 1 मई, 2025 से क्रियान्वित किया गया था।

कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 26 सितंबर 1975 को पारित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। परिणामस्वरूप, ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर, 2 अक्टूबर 1975 को, निम्नलिखित कार्यकाल के दौरान, पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी की सरकार इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करना था क्योंकि भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण है।

प्रथमा बैंक, जिसका मुख्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पहला आरआरबी था। इसे प्रायोजित किया गया थासिंडिकेट बैंक और इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी। अन्य चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गौर ग्रामीण बैंक (द्वारा प्रायोजित) थे। यूको बैंक), गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (प्रायोजित) भारतीय स्टेट बैंक), हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (प्रायोजित) पंजाब नेशनल बैंक), और जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक (द्वारा प्रायोजित)। यूको बैंक)।

भारत में गरीबी उन्मूलन और विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से इसके सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की आधारशिला रही है, जो इसके उत्पादन पैटर्न और उपभोग चक्र दोनों को आकार देती है। देश के शहरीकरण और औद्योगीकरण के बावजूद, इसकी लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है (आरबीआई, 2012)। ये ग्रामीण क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी ढाँचे तक अपर्याप्त पहुँच सहित गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन बाधाओं को दूर करना न केवल ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए, बल्कि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक सशक्तिकरण के एक प्रेरक के रूप में ऋण के महत्व को समझते हुए, भारत के नीति निर्माताओं ने ग्रामीण आबादी के लिए संस्थागत वित्त तक पहुँच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है।

परंपरागत रूप से, ग्रामीण परिवार अनौपचारिक ऋण प्रणालियों पर निर्भर थे, जिन पर साहूकारों का प्रभुत्व था, जो अक्सर उँची ब्याज दरों और दमनकारी शर्तों के साथ उनका शोषण करते थे। सुलभ, किफायती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं की कमी ने ग्रामीण भारत में गरीबी के चक्र को जारी रखा। ग्रामीण बैंक, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 1970 के दशक में ग्रामीण ऋण वितरण में वित्तीय अंतर को पाटने के लिए एक संस्थागत प्रतिक्रिया के रूप में उभरे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1975 के तहत स्थापित, आरआरबी की अवधारणा ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती थी। वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी समितियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए, सहकारी बैंकों की व्यावसायिकता और बुनियादी ढाँचे को सहकारी समितियों की स्थानीयकृत ऋण देने की प्रथाओं के साथ जोड़ा गया। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को ग्रामीण भारत की समग्र विकास प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना था।

स्वतंत्रता के बाद, भारत की बैंकिंग रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं के विस्तार पर ज़ोर देने के लिए पहले से ही विकसित हो रही थी। 1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने सरकार को विकासात्मक उद्देश्यों की ओर बैंकिंग गतिविधियों को निर्देशित करने की अनुमति दी। हालाँकि, यह स्पष्ट था कि ग्रामीण उधारकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अकेले वाणिज्यिक बैंक अपर्याप्त होंगे, खासकर उन लोगों की जो पारंपरिक ऋण पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए, इस अपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गई, जिन्होंने उन दूरदराज के इलाकों में भी शाखाएँ स्थापित करके अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की, जहाँ पहले बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं थीं।

ग्रामीण बैंकिंग के आर्थिक प्रभाव

यद्यपि भारत में गरीबी कम करने के लिए सतत आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रहा है, फिर भी इस विस्तार के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। विश्व बैंक (2013) की रिपोर्ट है कि भारत की लगभग 25% आबादी अभी भी प्रति दिन \$1.90 से कम पर जीवन यापन करती है। क्या भारत के ग्रामीण गरीब आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक पुनर्गठन से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे यदि उनके पास वित्तपोषण तक आसान पहुँच हो? कई आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार, माइक्रोफाइनेंस, या बिना बैंक वाले लोगों को वित्तीय वस्तुओं का वितरण, कम आय वाले परिवारों के लिए जीवन रक्षक हो सकता है जो अपनी उत्पादन और रोजगार रणनीतियों को बदलना चाहते हैं। उनकी संपत्ति अधिक सुरक्षित हो जाती है, वे आर्थिक तूफानों का सामना करने में बेहतर होते हैं, और वे आर्थिक हाशिए के दुष्चक्र को तोड़ते हुए सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी चढ़ने के लिए पैसे उधार लेने में सक्षम होते हैं।

भारत में विशाल सामाजिक बैंकिंग प्रयोग ने इस परिवर्तन सिद्धांत के प्रति प्रारंभिक नीतिगत उत्साह को प्रतिबिंबित किया, और गरीबी पर इसके प्रभाव के अर्थ-प्रयोगात्मक आँकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वे दर्शाते हैं कि ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण ऋण और बचत में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, उन्हें संरचनात्मक परिवर्तन के कुछ कमज़ोर संकेत भी मिले हैं^४ फिर भी, प्रक्रियाओं की जाँच करने की उनकी क्षमता समेकित आँकड़ों पर उनकी निर्भरता के कारण बाधित होती है। उदारीकरण के बाद, भारतीय बैंकों को अपनी शाखाएँ खोलने के स्थान तय करने में काफ़ी छूट दी गई। परिणामस्वरूप, अधिकांश भारतीय बैंकों की शाखाएँ महानगरीय क्षेत्रों में विस्तारित हुईं।

ग्रामीण भारत से प्राप्त हमारे आधारभूत आँकड़ों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि अधिकांश ग्रामीण परिवारों की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुँच नहीं है। विशेष रूप से, हमारे नमूने के 40% लोगों के पास शोध शुरू करने से पहले कोई औपचारिक ऋण नहीं था, और लगभग 20% के पास कोई औपचारिक बचत खाता नहीं था। आर्थिक उदारीकरण के बाद 25 वर्षों से भी अधिक समय तक, भारतीय अधिकारियों और वाणिज्यिक बैंकों ने गरीबों के लिए ग्रामीण के रूप में सूक्ष्म ऋण तक पहुँच बढ़ाने को प्राथमिकता दी। यह पैटर्न विकासशील देशों की तरह ही विद्वानों के अध्ययनों में भी सही साबित हुआ। 2000 के दशक के प्रारंभ से, निम्न-आय वाले परिवारों

पर सूक्ष्म ऋण के प्रभावों को मापने के उद्देश्य से प्रायोगिक अनुसंधान में वृद्धि हुई है। सूक्ष्म ऋणों तक पहुँच बढ़ाने के प्रभाव का अध्ययन कई देशों में किया गया है, जिनमें दक्षिण अफ्रीका (2010), भारत (2015) और मोरक्को (2015) शामिल हैं।

ग्रामीण समाज पर बैंकिंग का प्रभाव

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत 18वीं शताब्दी से हुई। भारत का पहला बैंक 1770 ई. में "बैंक ऑफ हिंदुस्तान" के रूप में शुरू हुआ और 1829-32 ई. में इसका परिसमापन हो गया। फिर, 1786 ई. में "जनरल बैंक ऑफ इंडिया" के रूप में एक और भारतीय बैंक की स्थापना हुई। भारत में बैंकिंग प्रणाली का कोई लंबा इतिहास नहीं है क्योंकि यहाँ वस्तु विनिमय पद्धति का उपयोग किया जाता था। भारतीय कृषि बैंकिंग का विकास 1975 से शुरू हुआ। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधियों का विस्तार करना था। बैंकिंग क्षेत्र ने ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार (GoI) कृषि बैंकिंग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। 1975 में, RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकिंग का विस्तार करने और किसानों को बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) की स्थापना की। इसके बाद 1982 में, RBI ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, कृषि नीतियों और योजनाओं को उनके पक्ष में लागू करने के लिए एक नए कृषि वित्त निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना की।

निष्कर्ष

भारत के बैंकिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शहरी सहकारी बैंकिंग उद्योग है। शहरी गरीबों और अन्य हाशिए के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में मदद करने के लिए, शहरी सहकारी बैंक एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। 1976 में, भारतीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए क्रेडिट की कमी को दूर करने में मदद करने के लिए आरआरबी अधिनियम पारित किया। इन बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के नाम से जाना जाता था। ग्रामीण पुनर्विकास बोर्ड "ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए क्रेडिट प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के उद्देश्य से बनाए गए थे।" वाणिज्यिक बैंक भारत के बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जिसमें निजी और सरकारी दोनों संस्थान शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार (GoI) कृषि बैंकिंग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। ग्रामीण भारत के लोगों के पास अब पहले की तुलना में अधिक पैसा खर्च करने और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने की अधिक इच्छा है।

संदर्भ

- डॉ. हरलया और श्रीरामन, ऐथल (2022). भारत में आर्थिक विकास पर बैंकों का प्रभाव. शेटी, मेघा और भट, सुधींद्र (2022) भारत में ग्रामीण बैंकिंग के विकास पर एक केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ केस स्टडीज इन बिज़नेस, आईटी एंड एजुकेशन। 346-357. 10.47992/IJCSBE.2581.6942.0201।
- विवोहो, जमाल और सपुत्रो, नुगरोहो और पामंगकास, पुत्रा और त्रिनुगरोहो, इरवान और एरिफियांटो, डोडी और गोएस्टजाहजंती, फ्रांसिस्का। (2021) ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय आर्थिक विकास: इंडोनेशिया से साक्ष्य। बिजनेस एंड सोसाइटी का इंटरनेशनल जर्नल. 22. 818-827. 10.33736/आईजेबीएस.3761.2021।
- गौतम, राहुल और भीमावरपु, वैकट मृदुला और रावल, आशी (2022) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारत में गरीबी उन्मूलन पर उनके प्रभाव पर अध्ययन। 5. 221-229.
- सैयद, मज़दी (2019). भारत में गरीबी और रोजगार पर ग्रामीण बैंकिंग का प्रभाव. 10.13140/RG.2.2.33612.16004.
- टोंगुराई, जित्तिमा और विथेसोंथी, चैपोर्न (2018)। आर्थिक संरचना और विकास पर बैंकिंग क्षेत्र का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विश्लेषण समीक्षा। 56. 10.1016/j.irfa.2018.01.002।
- आई बी, चिरप्पा और जे जी, नागवेनी (2020). भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका: एक अध्ययन।
- त्सकपोर्नु, रेवरेंड प्रो. नेल्सन (2017) घाना में आर्थिक विकास पर ग्रामीण बैंकिंग का प्रभाव। डॉ. नेल्सन क्वेसी त्सकपोर्नु। सामुदायिक विकास।
- प्राओ सेराफिन, याओ. (2019). वेमू देशों में बैंकिंग क्षेत्र के विकास पर शहरीकरण का प्रभाव: पैनेल क्वांटाइल रिग्रेशन से साक्ष्य. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस. 5. 105. 10.22158/jepf. v5n1p105.
- मोरी, मार्गेरिता. (2022) अध्याय 2 शहरी-ग्रामीण विभाजन के वित्तीय निहितार्थ. 10.9734/bpi/cabef/v5/4215A.

रेड्डी, ए. अमरेंदर (2010). समावेशी विकास के लिए ग्रामीण बैंकिंग रणनीतियाँ | भारतीय आर्थिक समीक्षा, पृ.8.

अमोआ, मैरी और ग्यामा,अम्मा (2014) ग्रामीण बैंकिंग अवधारणा] ग्रामीण घाना के विकास के लिए एक हस्तक्षेप.

अग्रवाल, प्रियंका (2020) वित्तीय समावेशन में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका. अनुसंधान - एनडीआईएम जर्नल ऑफ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च. 2. 20-25. 10.56411/अनुसंधान. 2020.v2i1.20-25.

राजेंद्रन, रत्चना और प्रोफेसर, रमानी (2020) भारत में सतत आर्थिक विकास और भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन - कारणात्मक संबंधों की खोज। 10. 156-163. 10.6084/m9.figshare.14129945.

करजालुओटो, हेइक्की और ग्लीवी-जियो, रिचर्ड और रामधोनी, दिनेश और शेख, ऐजाज़ (2020) उपभोग मूल्य और मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ: एक विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरी-ग्रामीण द्वंद्व को समझना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बैंक मार्केटिंग। 39. 272-293. 10.1108/IJBM-03-2020-0129